

लखनऊ, सोमवार
2 फरवरी, 2026
फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष 1
सं. 2082 वि.
वर्ष 79, अंक - 164 पृष्ठ 12
संस्करण : नगर
मूल्य : 4 रुपये

epaper : epaper.swatantrabharat.net

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया 53.47 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट

रक्षा बजट में 15% का इजाफा

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। वे 85 मिनट बोलीं, लेकिन आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। हालांकि टैक्स

- सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा
- 17 कैंसर मेडिसिन ड्रग्स की फ्री

फाइल करने में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और आयुर्वेदिक एम्स जैसी नई बातें कही हैं। बजट भाषण में कोई सीधा चुनावी ऐलान भी नहीं था। वे लोकसभा में तमिलनाडु की प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ी पहनकर पहुंचीं जरूर, लेकिन इसी साल होने वाले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी चुनाव पर सीधा असर डालने वाली घोषणाएं नहीं कीं।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में सीतारमण ने जियो-पॉलिटिक्स और चुनौतियों की बात कही और देश का रक्षा बजट रु. 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर रु. 7.85 लाख करोड़ कर दिया। यानी कुल रक्षा में 15.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। रक्षा बजट की खास बात यह है कि इसमें हथियार खरीदी के लिए आधुनिकीकरण पर पिछले साल के रु.1.80 लाख करोड़ के मुकाबले इस साल रु. 2.19 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। यह पूंजीगत खर्च में सीधी 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। सरकार ने रविवार को 2026-27 के लिए रक्षा व्यय के रूप में 7,84,678 करोड़ रुपये आवंटित किए, जबकि पिछले वर्ष यह राशि

6,81,210 करोड़ रुपये आवंटित की गई थी। कुल पूंजीगत व्यय 2,19,306 करोड़ रुपये आंका गया है। राजस्व व्यय 5,53,668 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जिसमें पेंशन के लिए 1,71,338 करोड़ रुपये शामिल हैं। पूंजीगत व्यय के तहत विमान और एयरो इंजन के लिए 63,733 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं, जबकि नौसेना बेड़े के लिए 25,023 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार ने 2025-26 में रक्षा बजट के लिए 6,81,210 रुपये आवंटित किए थे। पूंजीगत व्यय 1,80,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था, जो संशोधित अनुमान चरण में बढ़कर 1,86,454 करोड़ रुपये हो गया। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने असेन्य, प्रशिक्षण और अन्य विमानों के निर्माण के लिए आवश्यक घटकों और पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने रक्षा क्षेत्र की इकाइयों द्वारा रखरखाव, मरम्मत या नवीनीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले विमान के पुर्जों के निर्माण हेतु आयातित कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क माफ करने की भी घोषणा की। इन दोनों फैसलों से रक्षा और अंतरिक्ष उद्योग को मदद मिलने की उम्मीद है।

केंद्रीय बजट 2025 में रक्षा यानी डिफेंस क्षेत्र के लिए कुल 6.8 लाख करोड़ रुपये के बजट का ऐलान किया गया था।

2024 में भारत का रक्षा बजट 6.21 लाख करोड़ रुपये था। ये राशि वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 4.79 प्रतिशत ज्यादा थी। तब कुल 5.94 लाख करोड़ रुपये बजट का



आवंटन किया गया था।

बजट में रेलवे, विमानन और जल परिवहन क्षेत्रों के लिए कई बड़ी और दूरगामी घोषणाएं की गई हैं, जिनका उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना, लॉजिस्टिक्स लागत कम करना और आर्थिक विकास को गति देना है। केंद्रीय बजट 2026 में रेलवे को लेकर एक अहम फैसला लेते हुए सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की गई है। इन कॉरिडोरों के जरिए देश के प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्रों को तेज और आधुनिक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर इस प्रकार हैं: मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-

सिलीगुड़ी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले पांच वर्षों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे। इसकी शुरुआत ओडिशा के नेशनल वॉटरवे-5 से होगी, जो तालचेर और अंगुल जैसे खनिज-समृद्ध क्षेत्रों को कलिंगनगर औद्योगिक केंद्र और पारादीप व धर्मरा बंदरगाहों से जोड़ेगा। इससे पर्यावरण के अनुकूल और कम लागत वाले कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा। अंतर्देशीय जलमार्गों को मजबूत करने के लिए वाराणसी और पटना में शिप रिपेयर और मेंटेनेंस से जुड़ा एक आधुनिक इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही समुद्री विमान के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) योजना शुरू करने की भी घोषणा की

गई है। बजट 2026 में छोटे और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड लाने का ऐलान किया है। इससे उद्यमियों को अपने कारोबार के विस्तार में मदद मिलेगी। इसके अलावा, टेक्सटाइल सेक्टर को भी विशेष प्रोत्साहन देने की बात कही गई है, जिससे रोजगार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इंधन रिस्क गारंटी फंड बनाया जाएगा और कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम लॉन्च की जाएगी। साथ ही, जलमार्ग क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि इस सेक्टर में कुशल मानव संसाधन तैयार किया जा सके। मंत्रियों, मंत्रिमंडल सचिवालय और

पीएमओ के खर्च के लिए 1,102 6 5 करोड़ रुपये का आवंटन केंद्रीय बजट 2026-27 में मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तथा राज्य अतिथियों के आतिथ्य और मनोरंजन पर होने वाले खर्च के लिए 1,102 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 978.20 करोड़ रुपये से अधिक है। रविवार को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट में वित्त वर्ष 2026-27 लिए मंत्रिपरिषद के खर्चों के लिए 620 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में यह राशि 483.54 करोड़ रुपये थी। यह प्रावधान मंत्रिमंडल के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के वेतन, और अन्य भत्तों तथा यात्रा पर होने वाले व्यय के लिए है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 256.19 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 279.74 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। यह प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के प्रशासनिक खर्चों और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने के लिए है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के लिए



करोड़ रुपये तक आवंटित किए गए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 61.32 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

आम बजट 2026 के महत्वपूर्ण प्रस्ताव

- वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए
- इलेक्ट्रॉनिक मेन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव
- घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बनेंगे तीन रसायनिक पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क
- सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के जरिये तैयार उपकरण एवं सामग्री के उत्पादन पर जोर
- MSME क्षेत्र में चैप्टियन बनने के लिए कोष बनाने का प्रस्ताव
- ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों में लगेगी रियर अर्थ इकाइयां
- वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने के लिए कंटेनर विनिर्माण योजना का प्रस्ताव
- स्टील और सीमेंट जैसे क्षेत्रों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान
- नेचुरल यार्न स्कीम एवं रोजगार योजना और राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम का प्रस्ताव
- सरकारी वित्तीय संस्थानों को मजबूत करने के तहत REC, PFC के पुनर्गठन का प्रस्ताव।

बजट 2026-27 के सबसे बड़े बिंदु

एफएंडओ ट्रेडिंग पर एसटीटी बढ़ा शेयर बाजार के ट्रेडर्स के लिए बजट में झटका लगा है। सरकार ने पयूचर्स एंड ऑप्शंस (एफएंडओ) पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) बढ़ा दिया है।

विदेश यात्रा और पढ़ाई पर टीसीएस घटा मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए, सरकार ने विदेश यात्रा टैक्स और शिक्षा/चिकित्सा के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर टीसीएस (टीसीएस) की दर को घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया है। पहले यह दर काफी ऊंची (5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक) थी।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए पूंजीगत व्यय का लक्ष्य बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। वित्त वर्ष 2015 में यह मात्र 2 लाख करोड़ रुपये था, जो अब छह गुना बढ़ चुका है।

राजकोषीय घाटा का लक्ष्य सरकार ने वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.3 प्रतिशत तय किया है। वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों (आई) में यह 4.4 प्रतिशत आंका गया है। एफएमई के लिए रु.10,000 करोड़ का फंड छोटे उद्योगों को चैपियन बनाने के लिए तीन आयामी रणनीति अपनाई गई है। सरकार ने एक समर्पित रु.10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड बनाने की घोषणा की है। साथ ही, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के जरिए क्रेडिट गारंटी सपोर्ट भी दिया जाएगा।

शेयर बायबैक पर टैक्स नियम बदला कंपनियों द्वारा शेयरों के बायबैक से होने वाली आय को अब शेयरधारकों के हाथों में कैपिटल गेन्स माना जाएगा और उसी हिसाब से टैक्स लगेगा।

इंडस्ट्री और इनोवेशन : सेमीकंडक्टर और बायो-फार्मा मेन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) 2.0 और बायो-फार्मा शक्ति (बायो फार्मा) जैसी नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। साथ ही, रियर अर्थ परमानेंट मैनेट्स के लिए भी एक विशेष स्कीम लाई जाएगी।

कैंसर की दवाएं और कस्टम ड्रग्स स्वास्थ्य सेवा को किफायती बनाने के लिए कैंसर के मरीजों के लिए 17 दवाओं और औषधियों को बेसिक कस्टम ड्रग्स (बीसीडी) से छूट दी गई है। इसके अलावा, सोलर ग्लास और लिथियम-आयन बैटरी के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर भी कस्टम ड्रग्स में राहत दी गई है। **विदेशी संपत्ति का खुलासा के लिए छह महीने का मौका** छोटे करदाताओं के लिए एकमुश्त विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना (फॉरेन असेट डिक्लरेशन स्कीम) लाई जाएगी, जो छह महीने के लिए खुली रहेगी। इसके अलावा, 20 लाख रुपये से कम की अचल विदेशी संपत्ति का खुलासा न करने पर अब मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

कृषि और मत्स्य पालन मछुआरों को बड़ी राहत देते हुए भारतीय जहाजों द्वारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन (ईईजेड) में पकड़ी गई मछलियों पर ड्यूटी खत्म कर दी गई है। इसके अलावा, 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास की योजना भी बनाई गई है। बजट 2026-27 स्पष्ट रूप से युवा शक्ति और उत्पादन क्षमता पर केंद्रित है। जहां एसटीटी में बढ़ोतरी से बाजार में उतार-चढ़ाव दिख सकता है, वहीं टीसीएस में कटौती और कैपेक्स में वृद्धि से अर्थव्यवस्था के पहियों को गति मिलने की उम्मीद है।

बजट 2026 : क्या सस्ता और क्या महंगा

सस्ता	महंगा
खेल-कूद को सामान	शराब
कैंसर की 17 दवाएं	सिगरेट
7 गोपीर वीरमर्षियों की दवा	स्कूप
बीड़ी	खनिज
लेटर को प्रोडक्ट	पयूचर ऑप्शन ट्रेडिंग
जूते	
मोबाइल	
ईवी की बैटरी	
बायोगैस मिक्सर CNG	
माइक्रोवेव ओवन	
सोलर से जुड़े सामान	
कपड़े	

राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान

बजट अनुमान के अनुसार, 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि 2026-27 में यह घटकर 4.3 प्रतिशत होने की उम्मीद है। सरकार का फोकस वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास को गति देने पर है।

राज्यों को 1.4 लाख करोड़ की ग्रांट

बजट में राज्यों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2027 में राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाएगी। वित्त वर्ष 2027 के लिए डेट-टू-जीडीपी रेश्यो 55.6 प्रतिशत, जबकि नेट बॉर्रिंग 11.7 लाख करोड़ रुपए तय किया गया है।

शेयर बाजार में भारी गिरावट

वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान पयूचर्स और ऑप्शंस (एफएंडओ) ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (एसएसटी) बढ़ाने का ऐलान किया। इससे शेयर बाजार में जोरदार बिकवाली देखने को मिली और सेंसेक्स व निफ्टी में तेज गिरावट दर्ज की गई। बेंचमार्क सूचकांक और निफ्टी में करीब 2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1546.84 अंक या 1.88 प्रतिशत गिरकर 80,722.94 अंक पर आ गया। वहीं 50 शेयरों वाला निफ्टी 495.20 अंक या 1.96 प्रतिशत गिरकर 24,825.45 अंक पर आ गया।

इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं

केंद्रीय बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि नए इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और आयकर से जुड़े नियमों को पहले से अधिक सरल और पारदर्शी बनाया गया है। छोटे टैक्सपेयर्स के लिए एक नई स्कीम की भी प्रस्ताव रखा गया है, जिससे टैक्स अनुपालन आसान होगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दायित्व करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। इससे लाखों वेतनभोगी और छोटे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि फॉर्म को सरल बनाने के साथ-साथ टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया को भी डिजिटल और यूनजर-फ्रेंडली किया गया है। वित्त मंत्री ने संसद को बताया कि सरकार ने 2021-22 में किया गया वादा पूरा कर लिया है।

नवकांत ठाकुर

चाणक्य नीति की नसीहत के मुताबिक 'यो ध्रुवाणि परित्यज्य अधुवं परिषेवते। ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति चाधुवं नष्टमेव हि।' सामाजिक लोकोक्ति में इस श्लोक का भावार्थ यही है कि 'आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे।' लेकिन मसला है कि पूर्वजों की नसीहतों और समाज की समझाइश को उतना ही माना जाता है जितने से प्रत्यक्ष लाभ मिलता रहे। अलबत्ता जिस ज्ञान के अनुपालन में शांति, समरसता, संयम, संतोष, मर्यादा और अनुशासन की सीख छिपी हो उसकी अनदेखी कर देना ही लोग

बेहतर समझते हैं। तभी तो महाभारत का युद्ध टालने के लिए पांडवों को सिर्फ पांच गांव देने का संधि प्रस्ताव लेकर आए भगवान श्रीकृष्ण को दुर्योधन ने 'सूच्याग्र' नैव दास्यामी' यानी सुई की नोक के बराबर जमीन देने से भी यह कह कर इनकार कर दिया कि 'जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः, जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः।' यानी महाभारत के महायुद्ध की वजह बनी अपनी मनमानी जिद के गलत होने की हकीकत दुर्योधन भी जानता था, लेकिन भरी सभा में उसने खुले तौर पर कहा कि उसकी धर्म में प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म से निवृत्ति नहीं है। काश, दुर्योधन जैसी ही साफगोई

हमारे राजनेताओं में भी होती और वे खुल कर यह स्वीकार करते कि राजधर्म की अपेक्षाओं के विपरीत नीतियों पर अमल करना उनकी राजनीतिक विवशता है। यह

नजर और नजरिया

राजनीतिक विवशता ही तो है कि विकास के नाम पर कनिव्स रहने के मुश्किल और दुरूह कार ने चलकर बहुमत जुटाने के बजाय जाति-धर्म के नाम पर कन्स्यूज करके जनमत का अधिकतम धुवीकरण करने की रणनीति अपनाई जाए। वह भी तक जबकि यह सर्वविदित तथ्य है कि जाति-धर्म की राजनीति ऐसी दो-धारी तलवार

है जिसके इस्तेमाल में मामूली सी गलती भी आत्मघाती साबित हो सकती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूदा राजनीतिक माहौल में देखा जा सकता है जिसमें परंपरागत मतदाताओं के हितों की उपेक्षा करके लोकनिष्ठि यह है कि जान-बूझकर गलत कदम उठाने के बाद उसे सही बताने के लिए थेथरोलॉजी की इंतहा करने से भी गुरेज नहीं किया जा रहा है। तभी तो 'मिया' को पूरा मेहनताना नहीं देने की अपील करने वाले असम के मुख्यमंत्री विवाद बढ़ने पर गलती

मानने के बजाय यह दलील देते फिर रहे हैं कि मियां मुसलमानों को नहीं बल्कि बांग्लादेशी चुसपैठियों को कहा जाता है। इसी प्रकार माघ मेले में संतों पर लाठी भानेने, उनकी चुटिया पकड़कर घसीटने और शंकराचार्य को गंगा स्नान किए बिना ही वापस लौटने के लिए विवश किए जाने के प्रकरण में बड़प्पन दिखाते हुए गलती मान लेने के बजाय वैचारिक विरोधियों को कालनेमि बताते हुए समाज को उनसे सावधान रहने के लिए कहा जाता है। यहां तक कि सवर्ण समाज को अत्याचारी और अन्य सभी को पीड़ित मान कर बनाए गए यूजीसी के नए नियमों की विभाजनकारी सियासी हकीकत खुल कर सामने आ जाने के बाद भी

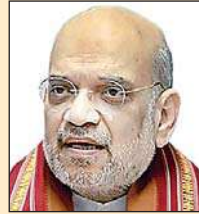
उसे वापस लेने के बजाय उसका सार्वजनिक तौर पर उसका बचाव करते हुए आश्वस्त किया जाता है कि किसी को भी इसका दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा। बहरहाल, समाज को जाति और धर्म के नाम पर लड़ा-भिड़ाने अपना सियासी उल्लू सीधा करने की जुगत भिड़ाने वालों से महावीर प्रसाद 'मधुप' के शब्दों में यही गुजारिश की जा सकती है कि- 'संविधान के ठेकेदारो! तनिक होश में आओ / पद-लोलुपता की दलदल में मन को नहीं फँसाओ / तार-तार होने से माँ का आँचल आज बचाओ / चौतरफा जो आग लगी है पहले उसे बुझाओ।' जैसी नजर, वैसा नजरिया।

ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है बजट
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज का बजट ऐतिहासिक है। इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला जी ने लगातार नौवां बार देश का बजट प्रस्तुत कर नया रिकॉर्ड बनाया है। ये बजट अपार अवसरों का राहमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है। ये भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव को भी सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा और गति मिलेगी।



बजट में नए भारत व विकसित भारत की संकल्पना
स्वतंत्र भारत ब्यूरो, लखनऊ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बजट में नए भारत व विकसित भारत की संकल्पना साफ दिखती है। रेल कॉरिडोर, आनुष और हेल्थ सेक्टर को महिलाओं पर केंद्रित करके जोर देना सराहनीय है। उन्होंने कहा कि छात्राओं या फिर कामकाजी महिलाओं के लिए, स्टैटिक्स से जुड़ी छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण करना, युवाओं के सपने को नई उड़ान देने के लिए, हर सेक्टर में अवसर उपलब्ध हो, इसका ध्यान रखा गया है। सीएम ने कहा कि यह बजट आम नागरिक के जीवन को सहज और सरल बनाने में सहयोग करेगा। अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने में सहायक होगा।

विकसित भारत का गोल्डन रोड मैप
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना करते हुए इसे 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का रोडमैप बताया और अगले 25 वर्षों के लिए दिशा-निर्देश प्रस्तुत किए। एक्स पर एक पोस्ट में शाह ने कहा कि बजट यह दर्शाता है कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत का सपना केवल एक नारा नहीं बल्कि सक्षम का दृढ़ संकल्प है।



सुधार से इंकार करने वाला बजट
कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट की आलोचना करते हुए कहा है कि आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है। किसान भी परेशान हैं। यह एक ऐसा बजट है, जो सुधार करने से इनकार करता है, भारत के असली संकटों से अनजान है। इससे पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026 को पेश किया।

आम आदमी का जिद्ध है, न फिद्ध : अखिलेश
केंद्रीय बजट प्रस्तुत होने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपाई बजट आते ही शेयर बाजार धड़म हो गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, इस बजट में न आम जनता का जिद्ध है न फिद्ध। जब भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, तो उसके बजट से क्या होगा। हम तो भाजपा के हर बजट को 1/20 (एक बटे बीस) का बजट मानते हैं क्योंकि वह 5 प्रतिशत लोगों के लिए होता है।

दिशाहीन, बंगाल के लिए कुछ नहीं : ममता
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे दिशाहीन बताया। केंद्रीय बजट 2026-27 दिशाहीन है, इसमें दूरदर्शिता का अभाव है और बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है।

इलाज, रिसर्च, मेडिकल टूरिज्म व आयुष को मिली उड़ान

लखनऊ को भी जगी आस, 188 गांवों में हो सकेगा विकास

टियर-2 में शामिल राजधानी को 5000 हजार करोड़ में मिलेगी भागीदारी

स्वतंत्र भारत, ब्यूरो, लखनऊ। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बजट 2026-27 एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया है। पहली बार देश का हेल्थकेयर बजट 1 लाख करोड़

12 साल में 176 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी

रुपये के आंकड़े को पार कर गया है। यूनियन बजट 2026-27 में हेल्थ सेक्टर के लिए कुल 1,04,599

करोड़ का प्राविधान किया गया है। बजट में इलाज, रिसर्च, मेडिकल टूरिज्म, आयुष और जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं हर पहलू को छूने की कोशिश की गई है। 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र को दिए गए 1,04,599 करोड़ रुपये पिछले साल के मुकाबले बढ़ा इजाफा है। 2025-26 में हेल्थ मिनिस्ट्री को 98,311 करोड़ मिले थे. अगर पिछले दस वर्षों पर नजर डालें, तो 2015 में हेल्थ बजट सिर्फ

34,286 करोड़ रुपये था, जो अब लगभग 191 प्रतिशत बढ़ चुका है। यह दिखाता है कि सरकार ने हेल्थ सेक्टर को धीरे-धीरे मजबूत करने की ठोस रणनीति अपनाई है। इस बार का हेल्थ बजट ऐतिहासिक रहा, जो कि 2025-26 के संशोधित

अनुमान से 8.96 प्रतिशत ज्यादा है। पिछले 12 सालों में स्वास्थ्य बजट में कुल मिलाकर 176 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।

जिला अस्पतालों में 50 प्रतिशत क्षमता बढ़ेगी

बजट में यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रौमा केयर सेंटर बनाकर उनकी क्षमता 50त तक बढ़ाई जाएगी। इससे गंभीर मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा और बड़े शहरों पर निर्भरता कम होगी। साथ ही बुजुर्गों के लिए जैरियाट्रिक केयर सिस्टम को भी मजबूत किया जाएगा।

आयुष और ट्रेडिशनल मेडिसिन पर फोकस

सरकार ने आयुष सेक्टर को भी मजबूती देने का ऐलान किया है। इसके तहत तीन नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्थापित किए जाएंगे। आयुष फार्मेसी और ड्रग टेस्टिंग लेब्स को अपग्रेड किया जाएगा। गुजरात के जामनगर स्थित ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को और आधुनिक बनाया जाएगा। इससे आयुर्वेद और ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी।

मुख्य इलाकों तक सीमित नहीं बल्कि हर उस मोहल्ले और गांव तक पहुंचेगा, जो अब तक सिस्टम की अनदेखी का शिकार रहा है। केन्द्रीय बजट में लखनऊ को भी तोहफा मिला है। टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए 5000 करोड़ रुपये के प्राविधान ने लखनऊ के उन 188 गांवों में विकास की उम्मीद जगा दी है जो अभी मूलभूत सुविधाओं की कतार से दूर हैं। अब इन शहरों में सड़क, सीवेज, ड्रेनेज और स्ट्रीट लाइट की चमक-दमक होगी। बता



दी कि 188 गांव, जो वर्ष 2019-20 में लखनऊ नगर निगम की सीमा में शामिल किए गए थे, आज भी सड़क, सीवेज, ड्रेनेज और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं या बदहाल हालात में हैं। नगर निगम सीमा में शामिल होने के बाद इन गांवों को शहर जैसी सुविधाएं मिलने की उम्मीद थी, लेकिन हकीकत इसके उलट रही। कहीं कच्ची सड़कें हैं, तो कहीं नालियां जाम पड़ी हैं। स्ट्रीट लाइटें या तो लगी ही नहीं या फिर वर्षों से खराब हैं। बारिश में जलभराव लोगों की दिनचर्या

टियर-2 शहरों की श्रेणी में शामिल है। उम्मीद है कि राजधानी को भी विकास कार्यों के लिए बड़ी राशि आवंटित होगी, जिससे वर्षों से उपेक्षित क्षेत्रों में काम शुरू हो सकेगा। लखनऊ को इस योजना का लाभ मिलता है तो सबसे पहले उन इलाकों पर ध्यान दिया जाएगा, जहां आज भी सड़कें टूट चुकी हैं, सीवेज लाइनें अधूरी हैं और ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हैं। मजबूत ड्रेनेज सिस्टम से जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी, वहीं नई सड़कों से आवागमन आसान होगा।

बजट पर प्रतिक्रियाएं

मधुमेह और कैंसर की दवाओं के दामों में कमी स्वागत योग्य

विशेषकर मधुमेह और कैंसर की दवाओं की लागत में कमी से गरीबों को मदद मिलेगी। चिकित्सा उपकरणों की लागत में कमी से नए अस्पतालों की स्थापना और पहले से मौजूद अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार में आसानी होगी। गरीबों और बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना जारी रहेगी। एम्स सहित मेडिकल कॉलेजों का विस्तार एवं सुदृढीकरण तथा मेडिकल सीटों में वृद्धि भी स्वागत योग्य है।

प्रोफेसर डॉ. सूर्यकांत, केजीएमयू रेस्पिरेंटरी मेडिसिन विभागाध्यक्ष

चिकित्सा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव

कैंसर के इलाज को लेकर सरकार ने जो निर्णायक कदम उठाया है, वह लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की नई किरण है। 17 जीवन रक्षक कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क को पूरी तरह खत्म करना यह सुनिश्चित करेगा कि अब कोई भी मरीज पैसे के अभाव में अपना ट्रीटमेंट अधूरा न छोड़े। इलाज की इस सुगमता के साथ-साथ, मानसिक स्वास्थ्य को मुख्यधारा की चिकित्सा प्रणाली में लाना एक क्रांतिकारी बदलाव है।

डॉक्टर राजेन्द्र कुमार चौधरी, कैंसर विशेषज्ञ

बायोफार्मा में अनुसंधान को मिलेगी उड़ान

देश को वैश्विक बायोफार्मा निर्माण केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए बायोफार्मा शक्ति बनाये जाने की घोषणा स्वागत योग्य है। बायोलाॅजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पादन के लिए अगले पांच वर्षों में इको-सिस्टम का निर्माण और केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को मजबूत किए जाने, 3 नए नाइपर बनने से फार्मा अध्ययन, नवाचार और अनुसंधान क्षेत्र मजबूत होगा।

सुनील यादव, फार्मसिस्ट फेडरेशन अध्यक्ष



आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूर्ण करेगा बजट : पंकज

स्वतंत्र भारत ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आम बजट को लेकर कहा कि यह गरीब, मध्यमवर्ग, महिला, युवा व वंचित वर्ग के आर्थिक और सामाजिक उत्थान की मजबूत कड़ी है। यह बजट जन-जन की आत्मनिर्भरता से आत्मनिर्भर विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि प्रदान करेगा। दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकास की एक नई परिभाषा रचने जा रहा है। दिल्ली-वाराणसी समेत 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-खिलीगुड़ी में भी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। यह पहल आधुनिक अवसरंचना,



आर्थिक प्रगति और भ र ो स ' म ' द कनेक्टिविटी का सशक्त प्रतीक है। इससे पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 15 वर्षों में पांच औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर के लिए 20 हजार करोड़ का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए किए गए प्रावधान किसानों की आय बढ़ाने और गांवों के समग्र विकास में सहायक होंगे। यह बजट कोकोनट, काजू और कोको जैसे कृषि-आधारित उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।

सात दुर्लभ बीमारियों को भी बजट में राहत : ब्रजेश पाठक

स्वतंत्र भारत, ब्यूरो, लखनऊ। संसद में प्रस्तुत बजट करोड़ों देशवासियों के संकल्पों की सिद्धि करने वाला बजट है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करेगा। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश के लिए बजट में विशेष प्रावधान रखे गए हैं। यह कहना है प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। रविवार को केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद डिप्टी सीएम ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि



केन्द्रीय बजट 2026-27 सर्वस्पर्शी, सर्व समावेशी, विकासोन्मुखी एवं करोड़ों देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सदन में प्रस्तुत इस बजट ने सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारी सरकार का संकल्प है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला यह बजट एक ऐसे भारत के निर्माण का विजन है, जो विश्व में हर क्षेत्र में अग्रणी होगा।

बजट पर प्रतिक्रियाएं

17 कैंसर दवाओं में कस्टम ड्यूटी शून्य स्वागत योग्य

बजट में 17 कैंसर की दवाओं में कस्टम ड्यूटी शून्य कर दी गई है। इसका लाभ मरीजों को मिलेगा। सरकार स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र के ढांचे को सुधार रही है यह स्वागत योग्य है। खासकर गरीब मरीज जो कैंसर से जुझ रहे हैं उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी।

डॉक्टर वरुण विजय, चिकित्सा अधीक्षक, कल्याण सिंह कैंसर संस्थान

कर्मचारी शिक्षक पेंशनर्स समुदाय के लिए आशाजनक फैली

बजट कर्मचारी शिक्षक पेंशनर्स समुदाय के लिए आशाजनक है। लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी कि सरकार बजट में 8वें वेतन आयोग के विचारणीय विषय में पुराने पेंशनर्स को शामिल करने, आयकर स्लैब में बदलाव करने आदि के सम्बन्ध में कुछ घोषणा करेगी पर सरकार ने इस पर कुछ नहीं कहा जो एक बड़े समुदाय के लिए निराशाजनक है।

बी.एन.कुशवाहा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उ.प्र.

युवाओं के रोजगार के लिए भी कोई रोड मैप नहीं

बजट में शिक्षकों, कर्मचारियों के सबसे बड़े मुद्दे ओपीएस पर कोई बात नहीं की गई। टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं। युवाओं के रोजगार के लिए भी कोई ठोस रोड मैप नहीं है। निजीकरण की तरफ देश को ले जाया जा रहा है। महंगाई से राहत दूर-दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही। निम्न और मध्य वर्ग में के लिए बजट में कुछ नहीं है और वह बेहद निराशा में है।

विजय कुमार बन्धु राष्ट्रीय अध्यक्ष, अटेवा



काशी पर जोर बाकी इग्नोर

केन्द्र में सत्तासीन मोदी सरकार ने रविवार को अपना बजट पेश किया। इस बजट में यूपी पर विशेष फोकस दिया गया है, जिसमें 2027 की चुनावी शुश्रूषा आ रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी को एक बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है। यहां शिप रियेपर इकोसिस्टम विकसित कर गंगा आधारित परिवहन और रोजगार को बढ़ावा देने की कोशिश की गयी है। साथ ही वाराणसी रिंग रोड हाइब्रिड रेल कॉरिडोर और काशी से दिल्ली तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। जिसके पीछे कनेक्टिविटी और व्यापार दोनों की गति मिलने की संभावना जतायी गयी है। इसके अलावा वाराणसी में एकीकृत लॉजिस्टिक हब के निर्माण का भी प्रस्ताव है, जिससे पूर्वांचल को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने में मदद मिलेगी। खास बात यह है कि इस बजट में प्रदेश के अन्य किसी जनपद का नाम तक नहीं लिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इमरजेंसी ट्रौमा सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही

कैंसर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता करने का प्रावधान किया गया है। अब ग्रामीण महिलाओं के लिए 'शी मार्ट' बनाए जाने का प्रस्ताव है। हर जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए एक छत्रावास एवं दिव्यांग सहाय योजना के तहत समय पर सहायता, कृत्रिम अंग बनाने वाली कंपनियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में निवेश का प्रावधान किया गया है। केन्द्रीय बजट को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ए व अधिवक्ता अ फ म त श्रीवास्तव त्यागी ने बताया कि यूपी में 75 जिले हैं लेकिन पीएम के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी पर खासी मेहरबानी दिखायी गयी है। पहली बार बजट पेश करने के दौरान ही शेयर मार्केट एवं आसमान छूते सोने एवं चांदी के दामों में भारी गिरावट देखने को मिली। उन्होंने बताया कि उम्मीद थी कि आयकर दाताओं को राहत मिलेगी पर ऐसा नहीं हुआ। इस बजट में रोजगार, एवं किसानों की फसलों के लिए एमएसपी पर भी ध्यान नहीं दिया गया। इसे यदि सपनों का ही बजट कहा जा सकता है।

- राजेश सिंह



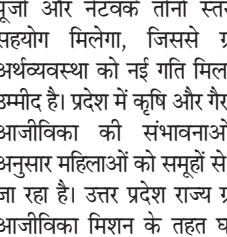
‘विकसित भारत 2047’ की दिशा में मजबूत बजट

स्वतंत्र भारत ब्यूरो, लखनऊ। केन्द्रीय बजट में उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं में नई उम्मीदें जगाई हैं। बजट में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर (शी-मार्ट्स) स्थापित करने के प्रस्ताव को यूपी में महिला सशक्तिकरण में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे ग्रामीण महिलाएं केवल ऋण-आधारित आजीविका तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि अपने उद्यमों की मालिक बनकर नई कहानी लिखेंगी। इससे प्रदेश में तीन करोड़ महिलाएं आत्म निर्भर बन सकेंगी। 'शी-मार्ट' का उद्देश्य महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए एक स्थायी मंच उपलब्ध कराना है। इसके लिए उन्नत और नवाचारी वित्तपोषण साधनों का उपयोग किया जाएगा। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ साझेदारी कर इस पहल को जमीन पर उतारेगी। 'लक्ष्मि दीदी' की सफलता के बाद अब महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को बाजार,



गांवों में खुलेंगे ‘शी-मार्ट’, महिलाएं बनेंगी उद्यमी

स्वतंत्र भारत ब्यूरो, लखनऊ। केन्द्रीय बजट में उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं में नई उम्मीदें जगाई हैं। बजट में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर (शी-मार्ट्स) स्थापित करने के प्रस्ताव को यूपी में महिला सशक्तिकरण में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे ग्रामीण महिलाएं केवल ऋण-आधारित आजीविका तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि अपने उद्यमों की मालिक बनकर नई कहानी लिखेंगी। इससे प्रदेश में तीन करोड़ महिलाएं आत्म निर्भर बन सकेंगी। 'शी-मार्ट' का उद्देश्य महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए एक स्थायी मंच उपलब्ध कराना है। इसके लिए उन्नत और नवाचारी वित्तपोषण साधनों का उपयोग किया जाएगा। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ साझेदारी कर इस पहल को जमीन पर उतारेगी। 'लक्ष्मि दीदी' की सफलता के बाद अब महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को बाजार,



रोशन होंगे तीर्थस्थल

बजट में 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर फोकस दिया गया है। इससे अयोध्या, गोरखपुर सहित लगभग 15 शहरों को रोशन किया जायेगा। इसके अलावा, छोटे-छोटे तीर्थ स्थलों के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। इससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सकेगी। इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ ही रोजगार के बड़े पैमाने पर अवसर उपलब्ध होंगे।

कर्मचारियों-पेंशनरों की उपेक्षा वाला बजट

स्वतंत्र भारत, ब्यूरो, लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने बजट 2026 पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इसमें न तो पेंशन व्यवस्था, न ही आठवें वेतन आयोग का कोई उल्लेख है। असंगठित, मानदेय व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की ईपीएफओ पेंशन और न्यूनतम वेतन बढ़ाने का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। वरिष्ठ नागरिकों की रेलवे रियायत बहाल नहीं होने और कर्मचारियों-शिक्षकों के हितों की अनदेखी के चलते उन्होंने इस बजट को कर्मचारी वर्ग के लिए निराशाजनक बताया।



एमाएसएमई, खादी वस्त्र पर जोर

केन्द्रीय बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और वस्त्रोद्योग को सशक्त बनाने के लिए दूरगामी प्रावधान किए गए हैं। वस्त्र क्षेत्र के लिए एक व्यापक और एकीकृत कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय फाइबर योजना, वस्त्र विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम, टेक्स-इको पहल और समर्थ 2 जैसी योजनाओं को शामिल किया गया है। साथ ही मेगा टेक्स्टाइल पार्कों की स्थापना से वस्त्र और परिधान उद्योग में प्रदेश में निवेश के नए अवसर खुलेंगे। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहा कि केन्द्रीय बजट उद्योग, किसानों और युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। बजट में खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। इस पहल के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के साथ-साथ कारीगरों और बुनकरों को स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत फंड में 2,000 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी डाली जाएगी।



epaper : epaper.swatantrabharat.net web portal : epaper.swatantrabharat.net

...इसलिए लाइन भेजे गए प्रभारी इंदिरानगर

कई थाना प्रभारी रडार पर हो सकती है कार्रवाई

स्वतंत्र भारत लखनऊ। वैसे रसूख हो तो नियम बेमानी हैं। यह मैं नहीं बल्कि लखनऊ कमिश्नरों के कई थानों पर तीन साल पूरा कर रहे वह थाना प्रभारी व अंडर ट्रांसफर थानाध्यक्ष हैं जो पुलिस मुख्यालय के आदेश को दरकिनार कर जमे हुए हैं। इंदिरानगर कोतवाल के लाइन हाजिर होना पुलिस विभाग में इस समय गर्माया हुआ है। खाकी से लेकर आम जनमानस तक अचानक लाइन हाजिर होने को लेकर वजह जानने को कोशिश में है। सूत्रों की माने तो इंदिरानगर के मानस इलाके में एक पार्क है जिसके चारों तरफ वीवीआईपी निवास करते हैं उस पार्क को मामूली अतिक्रमण से

मुक्त कराया जाना था और इसके लिए एलडीए ने नोटिस भेजकर फोर्स की मांग की थी। अफसरों के आदेश के बाद भी फोर्स नहीं दी गई और जब कारण पूछा गया तो फोर्स की कमी बताई गई। ऐसे में जब पूर्वी जोन के अफसर ने इस्पेक्टर से खुद क्यों न जाने की बात कही तो इस्पेक्टर ने आनन फानन में अपनी खानगी दिखा दी। हटाए जाने के कई कारण सामने आ रहे हैं जैसे इलाके के सुगा मऊ में स्थित एक फैक्ट्री है। बताया जा रहा है कि इंदिरानगर इस्पेक्टर अपने अफसरों की भी नहीं सुनते थे वहीं जानकारी बताते हैं कि इलाके में काफी चोरियां हुईं और खुलासा शून्य रहा। यही नहीं इलाके में नए

अपराधियों की कई गैंग पनपी जिस पर भी लगातार लगाने में असमर्थ रहे। ऐसे कई मामलों की शिकायत जब सीपी लखनऊ अमरेंद्र सेंगर तक पहुंची तो वह आग बबूला हो गए और उन्होंने इस्पेक्टर सुनील कुमार तिवारी को सीधे लाइन का रास्ता दिखा दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर लखनऊ अब एक्शन मोड पर आ गए हैं और जल्द ही वह भ्रष्टाचार की मिल रही शिकायतों को देखते हुए कई कोतवाली प्रभारियों को हटाने का मन बना चुके हैं। ऐसे में प्रभारी विहीन चल रहे कृष्णनगर, आलमबाग और इंदिरानगर थानों को इंचार्ज मिल सकेंगे।

मदरसे में लगी आग दमकलकर्मियों ने बच्चों को सुरक्षित बचाया

स्वतंत्र भारत ब्यूरो लखनऊ। ठकुरगंज थाना क्षेत्र के जैनैलगंज स्थित दारुल उलूम मदरसे में रविवार की दोपहर में अचानक से आग लग गई। समय रहते मदरसा संचालक ने पुलिस और दमकल को घटना की जानकारी दी आनन-फानन में दमकल कर्मियों ने पहुंचकर आग पर काबू करने के साथ वहां मौजूद करीब 150 बच्चों को सुरक्षित बचाने के साथ उनको वहां से आग से बचकर भागने में मदद की कोई जनहानि नहीं हुई है। दमकल कर्मियों ने दो घंटे में आग पर काबू पा लिया। एफएसओ ने बताया कि मदरसे की पहली मंजिल पर बने कमरे में दोपहर करीब 12 बजे आग की लपटें और धुआं निकलते देख वहां अफरा-तफरी के साथ शोशुल सुनकर मदरसे में रह रहे अन्य बच्चे भाग कर बाहर आ गए। कुछ ही मिनट में एफएसओ चौक दो गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंच गए। उनकी टीम ने कड़ी मशकत कर एक घंटे में आग पर काबू पा लिया। एफएसओ के मुताबिक आग कैसे लगी इस बात की जांच की जा रही है।

एडीजी कानून एवं व्यवस्था ने माघ मेला का किया निरीक्षण

अमिताभ यश ने भीड़ प्रबंधन व सुरक्षा व्यवस्था पर दिए निर्देश

स्वतंत्र भारत ब्यूरो लखनऊ। माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) उत्तर प्रदेश अमिताभ यश उनके स्टाफ अफसर सत्यसेन ने दो दिवसीय कैम्प करते हुए माघ मेला क्षेत्र का व्यापक भ्रमण व निरीक्षण किया। उस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ आवागमन, भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पान्टून पुल संख्या-01 से संगम नोज तक पैदल भ्रमण करते हुए श्रद्धालुओं की आवाजाही, भीड़ प्रबंधन एवं यातायात व्यवस्था की स्थिति को देखा। इसके बाद उन्होंने संगम नोज से बोट के माध्यम से जलमार्ग से त्रिवेणी संगम घाट, अरैल घाट, झूसी घाट, किला



घाट सहित अन्य प्रमुख घाटों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने आईसीसीसी (इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर) का भी अवलोकन कर तकनीकी निगरानी व्यवस्था और समन्वय प्रणाली की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवागमन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए कहा कि मेला क्षेत्र से निकासी मार्गों को निर्बाध रखा जाए, ताकि

किसी भी स्थान पर अवरोध उत्पन्न नहीं होने के साथ ही आकस्मिक स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पुलिस और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा, साइबर जागरूकता, खोया-पाया केंद्र तथा सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

खबर एक नजर

एसीपी बीकेटी के वाहन में मारी टक्कर, गनर घायल

स्वतंत्र भारत ब्यूरो लखनऊ। बकशी का तालाब थाना क्षेत्र के चंद्रिका देवी मोड़ के पास में रविवार दोपहर को एसीपी बीकेटी की सरकारी वाहन से किसी कार्य से क्षेत्र में भ्रमणशील थे उसी दौरान एक संदिग्ध वाहन का पीछा कर रहे थे उसी दौरान ओवरटेक करने के दौरान उनकी गाड़ी से इनोवा कार टच होने और अचानक ब्रेक लगाने से दुर्घटनाग्रस्त हो गईं हादसे में उनके सुरक्षाकर्मी को चोटें आईं जिनको प्राथमिक उपचार के बाद जाने दिया गया। जानकारी के मुताबिक एसीपी ज्ञानेंद्र सिंह एक संदिग्ध वाहन का पीछा कर रहे थे उसी दौरान चंद्रिका देवी मोड़ के पास एक इनोवा कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। जिससे उनके सुरक्षाकर्मी घनश्याम को मामूली चोटें आईं उन्हें आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत स्थिर होने के बाद जाने दिया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बीकेटी पुलिस इनोवा चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद एसीपी बीकेटी के निर्देश पर चालक को छोड़ दिया गया घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ है।

संदिग्ध हालात में बुजुर्ग की मौत
स्वतंत्र भारत ब्यूरो लखनऊ। थाना इंदिरानगर क्षेत्र के ईंशाफनगर कॉलोनी स्थित गौतमबुद्ध पार्क, सेक्टर-10 में रहने वाले 73 वर्षीय बुजुर्ग लाल प्रताप सिंह की उपचार के दौरान मौत हो गई। मामला संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ सेवन करने से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है।प्राप्त जानकारी के अनुसार 01 फरवरी 2026 को प्रातः करीब 09 बजे थाना इन्दिरानगर को चंदन हॉस्पिटल, विभूतिखंड से एक डेथ मेमो प्राप्त हुआ। मेमो में अवगत कराया गया कि उपचार के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। अस्पताल से मिली सूचना के अनुसार लाल प्रताप सिंह को 31 जनवरी 2026 की रात्रि लगभग 09 बजे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया गया कि उन्होंने किसी अज्ञात जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। चिकित्सकों द्वारा तत्काल उपचार शुरू किया गया, लेकिन रात्रि करीब 11:55 बजे उनकी मृत्यु हो गई।परिजनों के अनुसार 31 जनवरी की शाम लगभग 08 बजे मृतक की बहू जब उन्हें खाना देने उनके कमरे में पहुंची, तो उन्होंने देखा कि लाल प्रताप सिंह उल्टियां कर रहे थे। पृष्ठे पर उन्होंने स्वयं जहरीला पदार्थ सेवन करने की बात बताई। इसके बाद परिजन तत्काल उन्हें इलाज के लिए चंदन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे।परिजनों ने यह भी बताया कि लाल प्रताप सिंह प्रधनाध्यापक पद से सेवानिवृत्त थे। उनके परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री हैं। घटना की सूचना मिलते ही थाना इन्दिरानगर पुलिस ने अस्पताल और मौके पर पहुंचकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है।

कूटरचित दस्तावेजों से भूमि धोखाधड़ी का खुलासा

स्वतंत्र भारत ब्यूरो लखनऊ। पुलिस कमिश्नरने लखनऊ के दक्षिणी जोन अंतर्गत थाना मोहनलालगंज पुलिस ने कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से भूमि धोखाधड़ी के एक गंभीर मामले में फरार चल रहे शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा भूमि संबंधी अपराधों के विरुद्ध

भूमि का बेनामा अपने पक्ष में करा लिया गया है। शिकायतकर्ता ने स्पष्ट किया कि उनके या उनके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा कभी किसी के पक्ष में कोई बेनामा नहीं किया गया था।मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना मोहनलालगंज में मु0अ0स0 393/25 अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि रमेश कुमार गिरि, अगम और खुशीराम द्वारा फर्जी विक्रेता बनकर अपराध कारित किया गया था, जिन्हें 22 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त फर्जी गवाह बनी भगवान देई चौहान को भी 30 जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।प्रकरण में नामित अभियुक्त विमल गिरि लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिश और तलाश के दौरान 31 जनवरी 2026 को सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त मऊ तिराहा, थाना क्षेत्र मोहनलालगंज में मौजूद है। सूचना के आधार पर थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम ने तत्परा दिखाते हुए समय करीब 19:15 बजे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त को आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है, जबकि अन्य सलिस व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्यवाही जारी है।

इससे आहत होकर सुसाइड नोट में उसने लिखा कि मैं अच्छा और ईमानदार कर्मचारी हूं 500 के हिसाब में अपनी गलती छिपाने के लिए मैंने झूठ बोला। अब मौलिक की नजरों में मैं बेईमान साबित हो चुका हूं। बेईमानी और चोरी का दाग लेकर मैं जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए

उज्जाव जेल अधीक्षक से लाखों की टगी

स्वतंत्र भारत ब्यूरो लखनऊ। उज्जाव के जेल अधीक्षक को ही साइबर ठगों अपना शिकार बना लिया। बेटी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने का झांसा देकर 4 महीने में 50 लाख रुपए ठग लिए गए। जेल अधीक्षक जस्ट डायल के माध्यम से कंसल्टेंसी के प्रोपराइटर से संपर्क में आए थे। आरोपी ने उन्हें बाराबंकी के सफेदाबाद स्थित हिंद मेडिकल कॉलेज में सीट सुरक्षित कराने का आश्वासन देकर रकम ट्रांसफर कराने के बाद प्रोपराइट ने फोन बंद कर लिया फोन बंद होने पर वह लखनऊ स्थित उसके कार्यालय पहुंचे तो वह भी बंद मिला। जेल अधीक्षक ने कंसल्टेंसी संचालक और उसके साथियों के खिलाफ सदर्ज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है। उज्जाव जेल में तैनात जेल

अधीक्षक पंकज कुमार सिंह ने अपनी बेटी के नीट कार्डसलिंग के माध्यम से 'जस्ट डायल' का

- बेटी को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने का झांसा देकर फंसाया
- जस्ट डायल ने वेबसाइट से हटाई जानकारी

सहारा लिया। उनका संपर्क 'स्टडी पाथवे कंसल्टेंसी' के प्रोपराइटर अभिनव शर्मा से की उन्होंने मेडिकल कॉलेज बेटी का प्रवेश दिलाने में सहायता मांगी। अभिनव शर्मा ने उन्हें बाराबंकी के सफेदाबाद स्थित हिंद मेडिकल कॉलेज में प्रवेश सुरक्षित कराने का आश्वासन दिया। ड्राफ्ट के जरिए 20 लाख

रुपए ट्रांसफर किए पंकज कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि इस प्रवेश के एवज में, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नाम पर अलग-अलग तरीखों पर बड़ी धनराशि की मांग की गई। पीड़ित के मुताबिक, अभिनव शर्मा के कहने पर कुल 20 लाख रुपए के दो बैंक ड्राफ्ट बनाए गए। 18 जुलाई 2025 को को 10 लाख रुपए का पहला ड्राफ्ट बैंक के खाते से और दूसरा 19 जुलाई 2025 को 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट पंकज की पत्नी के खाते से बनाया गया। 30 लाख रुपए जमा कराए इसके अलावा, 24 अक्टूबर 2025 को अभिनव द्वारा बताए गए कोटक महिंद्रा बैंक, विभव खंड, गोमती नगर, लखनऊ के खाते में 30 लाख रुपए की राशि पंकज कुमार सिंह के खाते से ट्रांसफर की गई। ये सारे भुगतान उज्जाव शहर से किए गए थे।

रुपए ट्रांसफर किए पंकज कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि इस प्रवेश के एवज में, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नाम पर अलग-अलग तरीखों पर बड़ी धनराशि की मांग की गई। पीड़ित के मुताबिक, अभिनव शर्मा के कहने पर कुल 20 लाख रुपए के दो बैंक ड्राफ्ट बनाए गए। 18 जुलाई 2025 को को 10 लाख रुपए का पहला ड्राफ्ट बैंक के खाते से और दूसरा 19 जुलाई 2025 को 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट पंकज की पत्नी के खाते से बनाया गया। 30 लाख रुपए जमा कराए इसके अलावा, 24 अक्टूबर 2025 को अभिनव द्वारा बताए गए कोटक महिंद्रा बैंक, विभव खंड, गोमती नगर, लखनऊ के खाते में 30 लाख रुपए की राशि पंकज कुमार सिंह के खाते से ट्रांसफर की गई। ये सारे भुगतान उज्जाव शहर से किए गए थे।

दो ट्रक आपस में टकराए चालक घायल

स्वतंत्र भारत संवाददाता लखनऊ। सरोजनी नगर क्षेत्र में रविवार तड़के कोहरे के चलते कानपुर की ओर जा रहे ट्रक ने आगे-आगे चल रहे ट्रक में टक्कर मार दी। जिससे पीछे चल रहे ट्रक के चालक व उसका एक साथी घायल होकर केबिने में फंस गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से चालक को निकालकर अस्पताल पहुंचाया और दोनों ट्रकों को किनारे लगाकर आवागमन संचालित कराया। पुलिस के मुताबिक सरोजनी नगर के दोगा खेड़ा स्थित कानपुर रोड पर इटावा जिले के ऊचाहर निवासी 28 वर्षीय ट्रक चालक दीपक अपने कालीन विकास (कनौज निवासी) के साथ एक लुट लिया और उसे आलू के एक खेत में उसे बंधा हुआ फेंककर भाग गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस युवक से पूछताछ कर तहरीर के आधार पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस के मुताबिक सैरपुर क्षेत्र में ग्रामीणों की सूचना मिली कि एक पीड़ित हृदय नारायण कानपुर के घाटमपुर का रहने वाला है। वह खेत में बैठा रो रहा है और उसने लोगों को बुला रहा था यह देख लोगों ने उसके हाथ-पैर खोले।

थार से युवक का अपहरण कर मारपीट

स्वतंत्र भारत संवाददाता लखनऊ। शेरपुर थाना क्षेत्र में एक युवक को थार सवार लोगों ने उसे लिफ्ट के बहाने गाड़ी में बैठाकर बंधक बनाकर उसके हाथ-पैर करीब 60 हजार रुपए और फोन लूट लिया और उसे आलू के एक खेत में उसे बंधा हुआ फेंककर भाग गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस युवक से पूछताछ कर तहरीर के आधार पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस के मुताबिक सैरपुर क्षेत्र में ग्रामीणों की सूचना मिली कि एक पीड़ित हृदय नारायण कानपुर के घाटमपुर का रहने वाला है। वह खेत में बैठा रो रहा है और उसने लोगों को बुला रहा था यह देख लोगों ने उसके हाथ-पैर खोले।

उसने बताया कि यहां एलपीजी गैस की गाड़ी चलाता है। उसने बताया कि शनिवार रात वह आमौसी स्थित एलपीजी प्लांट से ट्रक लेकर कानपुर वापस जा रहे थे। रात करीब 9 बजे आमौसी में हाइड्रिल के पास वह गाड़ी का इंतजार कर रहा था उसी दौरान एक थार उनके पास आकर रुकी उसमें बैठे चार युवकों ने हृदय नारायण से कानपुर जाने के बारे में पूछा और लिफ्ट देते हुए उसे गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी को रिंग रोड की तरफ मोड़ दिया और एक युवक ने पिस्तौल निकालकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधने के साथ ही हाथ-पैर बांधकर पूरे रास्ते भर मारते-पीटते रहे और उसकी जेब में रखे 60 हजार रुपए छीन लिए।

22 साल के कार्लोस अल्काराज बने ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का फाइनल मुकाबला इतिहासिक रहा। स्पेन के 22 वर्षीय कार्लोस अल्काराज ने सर्बिया के 38 वर्षीय नोवाक जोकोविच को 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से हराकर

■ फ़ाइनल में जोकोविच को हराया

अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। अल्काराज का यह सातवां ग्रैंडस्लैम खिताब भी है।

पहले सेट में जोकोविच ने 6-2 से बढ़त बनाई और अपने अनुभव का लोहा दिखाया, लेकिन इसके बाद अल्काराज ने लगातार दो सेट 6-2 और 6-3 से जीतकर मैच में वापसी की। चौथे सेट में 7-5 से जीत दर्ज कर अल्काराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ अल्काराज ओपन एरा में करियर ग्रैंडस्लैम पूरा करने वाले छठे पुरुष



खिलाड़ी बन गए और 22 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल कर राफेल नडाल (24) का रिकॉर्ड तोड़ा। अल्काराज अब तक कुल सात ग्रैंडस्लैम खिताब जीत चुके हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन (2026), फ्रेंच ओपन (2024, 2025), विंबलडन (2023, 2024), और यूएस ओपन (2022, 2025)। जोकोविच अब 25वें ग्रैंडस्लैम खिताब से वंचित रहा। उनके नाम

कुल 24 ग्रैंडस्लैम खिताब हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलियन ओपन (10), फ्रेंच ओपन (3), विंबलडन (7) और यूएस ओपन (4) शामिल हैं। यह उनका 11वां ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल था, जिसमें उन्हें पहली बार हार का सामना करना पड़ा। अल्काराज की इस जीत ने उन्हें सबसे युवा करियर ग्रैंडस्लैम विजेता बना दिया है और टेनिस जगत में उनकी चमक को और बढ़ा दिया है।

टी-20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान मैच नहीं होगा

नई दिल्ली। टी-20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को मैच नहीं होगा। पाकिस्तान सरकार ने रविवार शाम को इस मैच के बॉयकॉट का ऐलान किया। दोनों टीमों ग्रुप स्टेज में कोलंबो में एक-दूसरे से भिड़ने वाली थीं। हालांकि, अब तक यह तय नहीं है अगर नॉकआउट में भारत सामने आया तो पाकिस्तान मैच खेलेगा या नहीं?

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने 24 जनवरी को बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में एंटी दी थी। ICC के इस फैसले के विरोध में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट कर दिया। जिसके बाद दृष्टष्ट पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहा है।

पाकिस्तान ने रविवार को घोषणा की कि वह टी-20 वर्ल्ड कप 2026

में हिस्सा लेगा, लेकिन भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करेगा। पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाने के बाद लिया। बांग्लादेश सरकार ने भारत में खेलने को लेकर सुरक्षा चिंता जताई थी। सरकार ने X पर एक पोस्ट में कहा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ICC वर्ल्ड T20 2026 में हिस्सा लेने की मंजूरी देती है। हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ होने वाले मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी। ICC ने देर रात 11 बजे मीडिया रिलीज में कहा, हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के ऑफिशियल कन्फर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। ICC सरकार के फैसलों का समर्थन करता है, लेकिन

पाकिस्तान का फैसला दुनियाभर में क्रिकेट के इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाला है। ICC उम्मीद कर रहा है कि PCB अपने फैसले पर फिर से विचार करेगा ताकि दुनियाभर में क्रिकेट का सिस्टम प्रभावित न हो। पाकिस्तान खुद ICC का सदस्य है। हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान किसी तरह सभी स्टेकहोल्डर्स को ध्यान में रखते हुए आखिरी फैसला ले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चीफ मोहसिन नकवी ने सोमवार, 26 जनवरी को प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में पाकिस्तान के वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन और भारत के खिलाफ मुकाबले को लेकर बातें हुईं। नकवी ने कहा था कि शुक्रवार या सोमवार तक आखिरी फैसला लिया जाएगा। अब रविवार को सरकार ने इस पर फैसला ले लिया।

बजट के बाद सेंसेक्स 1546 अंक गिरकर 80,722

नई दिल्ली। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर सिन्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (सूझ) बढ़ाने का ऐलान किया। इससे शेयर बाजार में जोरदार बिकवाली देखने को मिली और सेंसेक्स व निफ्टी में तेज गिरावट दर्ज की गई। बेंचमार्क सूचकांक और निफ्टी में करीब 2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई।

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स दोपहर के कारोबार में 2,370.36 अंक या 2.88 प्रतिशत गिरकर 80,000 के स्तर से नीचे 79,899.42 पर आ गया। बैरोमीटर 80,722.94 पर स्थिर हुआ, जिसमें 1,546.84 अंक या 1.88 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 495.20 अंक या 1.96 प्रतिशत गिरकर 24,825.45 पर बंद हुआ। दिन के दौरान इसमें 748.9 अंक या 2.95 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 24,571.75 पर पहुंचा।

एसटीटी को बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत वित्त मंत्री ने शेयर बाजार को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि छोटे शेयरधारकों की सुरक्षा के लिए बायबैक के टैक्स में परिवर्तन किया जाएगा। प्रमोटरों की ओर से दुरुपयोग को रोकने के लिए अतिरिक्त बायबैक कर का प्रावधान लाया गया। इससे कॉर्पोरेट प्रमोटरों



के लिए प्रभावी टैक्स 22 प्रतिशत और गैर-कॉर्पोरेट प्रमोटरों के लिए प्रभावी टैक्स 30 प्रतिशत हो जाएगा। सभी शेयरधारकों के बायबैक पर पूंजीगत लाभ के रूप में कर का प्रतीजोक्त है। वायदा सौदों पर एसटीटी को बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत किया गया। गैर कॉर्पोरेट प्रवर्तकों के लिए 30 प्रतिशत टैक्स लगाया गया। सभी शेयरधारकों के बायबैक पर पूंजीगत लाभ के रूप में कर का प्रस्ताव लाया गया।

क्या है विशेषज्ञों की राय? एक्सिस सिन्योरिटीज के एमडी और सीईओ प्रणव हरिदासन ने कहा कि हालांकि, बाजार में बेचैनी मुख्य रूप से एफएंडओ पर एसटीटी में वृद्धि, विशेष रूप से वायदा पर हुई तेज वृद्धि पर केंद्रित है। यह पिछले साल के उच्च पूंजीगत लाभ करों के बाद

आया है, जिससे बाजार प्रतिभागियों के लिए समग्र लेनदेन लागत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि फ्यूचर्स एक मार्जिनयुक्त, जोखिम प्रबंधित उत्पाद है और आमतौर पर खुदरा खरीदारों की अतिरिक्त आय का प्राथमिक स्रोत नहीं है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या उच्च एसटीटी वांछित परिणाम देगा या इसके बजाय तलता, भागीदारी और भारत का बाजार लागत प्रतिस्पर्धात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। हरिदासन ने आगे कहा कि विदेशी निवेशकों और घरेलू व्यापारियों द्वारा ये चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, और ये तत्काल बाजार प्रतिक्रिया में परिलक्षित होती हैं। चौंस इक्कीटी ब्रोकिंग के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक आकाश शाह ने कहा कि सिन्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स

1 अप्रैल से बदलेगा आयकर कानून, कर्माई व बचत पर क्या होगा असर?

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए 'विकसित भारत' की नींव को और मजबूत करने का रोडमैप साझा किया है। 'युवा शक्ति' और आर्थिक स्थिरता पर केंद्रित इस बजट का कुल आकार लगभग 53.5 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। सरकार ने विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे और मैन्युफैक्चरिंग पर सकाराी खजाना खोला दिया है, वहीं राजकोषीय अनुशासन को भी प्राथमिकता दी है। सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (गुड) के 4.3 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है, जो चालू वित्त वर्ष के 4.4 प्रतिशत के संशोधित अनुमान से कम है।

विदेश यात्रा और टैक्स फाउलिंग पर आम आदमी को बड़ी राहत

आम कर्दाताओं और मध्यम वर्ग को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने विदेश यात्रा और शिक्षा को किफायती बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने विदेश यात्रा पैकेज की बिक्री पर टीसीएस का दर 5 से 20 प्रतिशत के स्लैबर से घटाकर सीधे 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है। यही राहत लिलाइज्ड रेंमिटेंस स्कीम (एलएआरएस) के तहत शिक्षा और चिकित्सा के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर भी दी गई है, जहाँ अब टीसीएस की दर 2 प्रतिशत होगी।

खेल/आर्थिक

पिछली बार की तुलना में खेल बजट में 1133 करोड़ रुपये की वृद्धि, खेलो इंडिया पर फिर मेहरबान सरकार

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 2026-27 के लिए आम बजट पेश किया। इसमें युवा मामले और खेल मंत्रालय के आवंटन में 1000 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि की गई, जिसमें खेल सामग्री निर्माण क्षेत्र को बहुत लाभ हुआ है। पहली बार उन्हें 500 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है। खेल मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन 4479.88 करोड़ रुपये है जो 2025-26 के संशोधित आवंटन 3346.54 करोड़ रुपये से 1133.34 करोड़ रुपये अधिक है। राष्ट्रीय शिविरों के आयोजन और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए सामग्री उपलब्ध कराने वाले भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के लिए आवंटित राशि को 880 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 917.38 करोड़ रुपये कर दिया गया है। देशभर के स्टेडियमों के रखरखाव और उनके उपयोग की जिम्मेदारी भी साइ की होती है। हालांकि, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला और राष्ट्रीय डोपिंग-विरोधी एजेंसी का बजट क्रमशः 28.55 करोड़ रुपये से घटाकर 23 करोड़ रुपये और 24.30 करोड़ रुपये से घटाकर 20.30 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

खेल सामग्री उद्योग को बढ़ावा

सीतारमण ने अपने बजट भाषण में उच्च गुणवत्ता वाले और किफायती



खेल सामग्री के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की भारत की क्षमता पर जोर दिया और इस तरह से खेल मंत्री मनसुख मांडविया के दृष्टिकोण का समर्थन किया। उन्होंने कहा, 'मैं खेल सामग्री के लिए एक समर्पित पहल कर दिया गया है। देशभर के डिजाइन के साथ-साथ खेल सामग्री के क्षेत्र में विनिर्माण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।' अभी तक के बजट में खेल सामग्री क्षेत्र से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। खेल मंत्रालय ने इस आवंटन का स्वागत किया और कहा कि खेल सामग्री उद्योग के लिए समर्थन सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाएगी। इस पहल से 'मेक इन इंडिया' योजना के तहत देश में खेल सामग्री निर्माण करने वाले स्टार्टअप

भारत से हारकर विश्व कप से बाहर हुआ पाकिस्तान, 58 रनों से धोया; सेमीफाइनल में बनाई जगह

नई दिल्ली। भारत ने अंडर-19 विश्वकप के 36वें मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 252 रन बनाए। भारत ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए। हालांकि वेदांत त्रिवेदी के 68 रनों की दमदार पारी और अर्धिम ओवरों में कनिका, एम्विशि की महत्वपूर्ण पारियों की बदौलत भारत 250 के पार पहुंचने में सफल रहा। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम एक



समय मैच जीतने के रास्ते पर थी लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने दमदार वापसी करते हुए मैच भारत की

खेल बजट की अन्य घोषणाएं

राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के लिए आवंटित बजट भी 78.64 करोड़ रुपये से घटाकर 46.98 करोड़ रुपये कर दिया गया है। राष्ट्रीय खेल विकास कोष में योगदान राशि को तीन करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि सरकार ने इस वर्ष खिलाड़ियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 28 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40 करोड़ रुपये कर दिया है। राष्ट्रीय खेल संघों के लिए सहायता राशि में भी मामूली वृद्धि की गई है, जो 400 करोड़ रुपये से बढ़कर 425 करोड़ रुपये हो गई है। युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की धनराशि इस वर्ष 57.68 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 58.41 करोड़ रुपये कर दी गई है। युवा हॉस्टलों के आवंटन में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। यह पिछले साल के 1.10 करोड़ रुपये की तुलना में इस साल 19.20 करोड़ रुपये कर दी गई है। राष्ट्रीय सेवा योजना में भी भारी वृद्धि की गई है। इसे पिछले वर्ष के 275.00 करोड़ रुपये के मुकाबले इस वर्ष 357.39 करोड़ रुपये मिलेंगे।

करने के प्रस्ताव रखा जिससे जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए सरकार के प्रमुख खेलों इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। सीतारमण ने कहा कि यह मिशन आपस में जुड़े विभिन्न माध्यमों से एकीकृत प्रतिभा विकास कार्यक्रम को सुगम बनाएगा। खेलो इंडिया कार्यक्रम 2017 में शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभा पहचान के लिए सभी आयु वर्ग में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना था। सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण के दौरान कहा, 'खेल क्षेत्र रोजगार, कौशल विकास और नैकरी के अनेक अवसर प्रदान करता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम

से खेल प्रतिभाओं को निखारने की पहल को आगे बढ़ाते हुए, मैं अगले दशक में खेल क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव करने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं।' उन्होंने कहा, 'यह मिशन मूलभूत, मध्यवर्ती और विशिष्ट स्तरों के प्रशिक्षण केंद्रों के सहयोग से एकीकृत प्रतिभा विकास, प्रशिक्षकों और सहायक स्टाफ का व्यवस्थित विकास, खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एकीकरण, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और मंच प्रदान करने के लिए प्रतियोगिताएं और लीग का आयोजन तथा प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए खेल संरचना के विकास को सुगम बनाएगा।'

सोना-चांदी के दामों में दो दिन में भारी गिरावट, निवेशकों में चिंता का माहौल

दिया। पाकिस्तान 33.3 ओवर में यह लक्ष्य हासिल कर ही टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच सकता था। जिसमें वह विफल रहा। भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 46.2 ओवर में 194 के स्कोर पर समेट कर उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने समीर मिनहास (नौ) के विकेट गंवा दिया। खिलन पटेल ने मिनहास को पगबधा आउटकर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद उस्मान खान और हमजा

जहूर ने पारी को संभाला और 88 के स्कोर तक ले गये। 17वें ओवर में आयुष म्हात्र ने उस्मान खान (66) को आउट कर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद कप्तान फरहान यूसुफ ने मोर्चा संभाला।दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को 151 तक ले गये। पाकिस्तान 35.3 ओवरों तक पांच विकेट पर 168 रन ही बना सका। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण से जूझ रहे पाकिस्तानी बल्लेबाजों के धीमी प्रदर्शन के कारण पाकिस्तान टीम 33.3 ओवर में मैच जीतने में विफल रही।

सोना-चांदी के दामों में दो दिन में भारी गिरावट, निवेशकों में चिंता का माहौल

नई दिल्ली। भारत में सोना और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन तेज गिरावट दर्ज की गई है। 1 फरवरी को वायदा बाजार में चांदी लगभग 25 हजार रुपए (9 प्रतिशत) गिरकर 2.65 लाख रुपए प्रति किलो पर आ गई, जबकि सोने में भी करीब 12 हजार रुपए (8%) की गिरावट आई और 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1.38 लाख रुपए पर ट्रेड हुआ।

इससे पहले 30 जनवरी को भी सोने और चांदी की कीमतों में क्रमशः 9,545 रुपए और 40,638 रुपए की गिरावट दर्ज की गई थी। ऐसे में दो दिन में सोना कुल 31 हजार रुपए सस्ता हुआ, जबकि चांदी में 1.36 लाख रुपए की भारी गिरावट देखी गई।इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 1 फरवरी को सरफा बाजार में एक किलो चांदी 3,39,350 रुपए पर, जबकि सोना 10 ग्राम 1,65,795 रुपए पर बंद हुआ। इस गिरावट का असर गोल्ड और सिल्वर पर भी पड़ा, जिसमें क्रमशः 8प्रतिशत और 15प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई। विशेषज्ञों के अनुसार इस गिरावट के कई कारण हैं। सबसे पहले, प्रॉफिट बुकिंग ने बाजार पर दबाव बनाया, क्योंकि हाल



के दिनों में सोना-चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थीं। इसके अलावा, फिजिकल डिमांड में कमी और औद्योगिक उपयोग को लेकर बढ़ी चिंताएं भी दामों में गिरावट का एक बड़ा कारण बनीं। सेबी रजिस्टर्ड कमोडिटी एक्सचेंज अनुज गुप्ता ने बताया कि शिकागो मर्केटाइल एक्सचेंज ने सोने और चांदी पर मार्जिन मनी बढ़ा दी है। सोने का मार्जिन 6प्रतिशत से बढ़ाकर 8प्रतिशत और चांदी का 11प्रतिशत से 15प्रतिशत कर दिया गया है। मार्जिन बढ़ने का मतलब है कि ट्रेडर्स को पहले से खरीदी गई वस्तु पर अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। यदि उनके पास तुरंत पैसा नहीं है तो उन्हें अपना सोना या चांदी बेचना पड़ता है,

जिससे दामों पर और दबाव बनता है।विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुकिंग और बड़े हुए मार्जिन की वजह से बाजार अस्थिर बना हुआ है। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि फिलहाल लंबी अवधि की योजनाओं और निवेशवाजी में सोना-चांदी खरीदने या बेचने से बचें। सोने और चांदी की गिरावट ने बाजार में हलचल पैदा कर दी है और विशेषज्ञों ने कहा कि आगामी दिनों में वैश्विक वित्तीय संकेतकों और स्थानीय मांग की स्थिति के अनुसार ही कीमतों में स्थिरता या और गिरावट देखने को मिल सकती है।

सोयाबीन और बिनौला तेल के भाव में बढ़त, तिलहन कमजोर

नई दिल्ली। विदेशी बाजारों में मजबूती और पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव से आपूर्ति प्रभावित होने के चलते देश के तेल-तिलहन बाजारों में तेजी का रुख देखा गया। सोयाबीन और बिनौला तेल के भाव में सुधार रहा जबकि डी-आयलंड केक (डीओसी) की कमजोर मांग के चलते सोयाबीन तिलहन में गिरावट दर्ज की गई। सरसों, मूंगफली तेल तिलहन, कच्चा पामोएल (सीपीओ) और पामोलीन तेल के भाव पूर्व स्तर पर बंद हुए। बाजार सूत्रों के अनुसार इस बार खपत बढ़ने के बावजूद घरेलू बाजारों पर इसका असर नहीं पड़ा है। नवंबर-दिसंबर 2022 में कुल 31.11 लाख टन (खाद्य व अखाद्य) तेलों का आयात हुआ था जबकि नवंबर-दिसंबर 2023 में यह घटकर 24.72 लाख टन रह गया यानी करीब 21 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है और देश के बंदरागारों पर सोयाबीन तेल आने में 40 से 45 दिन का समय लग रहा है। विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों के दाम नरम रहने के बावजूद घरेलू बाजारों पर इसका असर नहीं पड़ा है, जिससे संकेत मिलता है कि देश में खाद्य तेलों का स्टॉक सीमित है। सूरजमुखी और सोयाबीन जैसे सॉफ्ट तेलों की आपूर्ति कम है और जाड़े व विवाह-शادی के मौसम में मांग बढ़ने से आपूर्ति



की दिकतें बढ़ सकती हैं। यह स्थिति देशी तेल-तिलहन उत्पादन बढ़ाने की जरूरत को रेखांकित करती है। देश की एक प्रमुख तेल कंपनी पामोलीन तेल के 770 ग्राम के पाउच को 85 रुपये के अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेच रही है, जिससे पामोलीन तेल का भाव 120 रुपये प्रति किलो बैठा है जबकि इसका आयात मूल्य 85 रुपये प्रति किलो है। गरीब वर्ग, जो पामोलीन तेल का अधिक उपयोग करता है, इस बढ़ी लागत का बोझ उठाने को मजबूर है। विशेषज्ञों ने कहा कि तेल संपन्नता और सरकार को केवल थोक बाजार नहीं बल्कि खुदरा बिज्नी मूल्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तेल-तिलहनों के भाव इस प्रकार रहे - सरसों तिलहन 5,415 से 5,465 रुपये प्रति क्विंटल, मूंगफली 6,665 से 6,740 रुपये प्रति क्विंटल, मूंगफली तेल मिल डिलीवरी (गुजरात) 15,750 रुपये प्रति क्विंटल, मूंगफली रिफाईंड तेल 2,350 से 2,625 रुपये प्रति टन, सरसों तेल ददरी 10,025 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों यानी तेल 1,710 से 1,810 रुपये प्रति टन, तिल तेल 18,900 से 21,000 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन तेल (हिल्ही) 10,075 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन मिल डिलीवरी (इंदौर) 9,825 रुपये प्रति क्विंटल रहा।

